ई संदेश

05 फरवरी, 2026 | अंक -191

सात दिन, सात पृष्ठ

प्रदेश की खुशहाली, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में उद्योग जगत सबसे बड़ा सहयोगी : मुख्यमंत्री

सभी बैंक विकासोन्मुख क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाएँ, नागरिकों को सरल और समयबद्ध सेवा प्रदान करें : मुख्यमंत्री

केन्द्रीय बजट 2026-27 किसान, युवा, महिला और गरीब आदि की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया : मुख्यमंत्री

सीता माता के उज्ज्वल चरित्र से नई पीढ़ी को परिचित कराना समय की आवश्यकता:मुख्यमंत्री

ऐसी बीज नीति तैयार की जाए, जो आने वाले वर्षों की कृषि चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करे : मुख्यमंत्री

'गन्ना आधारित अंत: फसली खेती' उत्तर प्रदेश के कृषि भविष्य का नया मॉडल : मुख्यमंत्री

'सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेण्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन' प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और उद्यमिता का एक सशक्त केंद्र बनेगा : मुख्यमंत्री

प्रदेश में फार्मा सेक्टर के लिए बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर,सबसे बड़ा कन्ज्यूमर मार्केट और वर्कफोर्स उपलब्ध : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 29 जनवरी, 2026 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

प्रदेश की खुशहाली, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में उद्योग जगत सबसे बड़ा सहयोगी : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 31 जनवरी, 2026 यहां लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी) में राज्य स्तरीय उद्योग संगठनों और प्रमुख उद्यमियों के साथ आहूत एक विशेष बैठक में कहा कि उत्तर प्रदेश में किया गया निवेश केवल एक राज्य में निवेश नहीं, बल्कि राष्ट्रहित में किया गया निवेश है। आज उत्तर प्रदेश जिस आर्थिक मजबूती और स्थिरता की ओर बढ़ रहा है, उसमें उद्योग जगत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश की खुशहाली, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में उद्योग जगत सबसे बड़ा सहयोगी है और सरकार इस साझेदारी को और मजबूत करना चाहती है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार उद्योगों को केवल निवेश नहीं, बल्कि विकास की साझेदारी का अभिन्न हिस्सा मानती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में निवेश करने वाला प्रत्येक उद्यमी, सरकार को अपने साथ खड़ा पाएगा और नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा प्रशासन तीनों स्तरों पर सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने उद्योग समूहों से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास और सामाजिक बदलाव का सहभागी बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न उद्योग समूह अपनी रुचि और विशेषज्ञता के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में सी0एस0आर0 के तहत योगदान कर सकते हैं। सरकार उद्योगों के सामाजिक योगदान को प्रदेश के समावेशी विकास का मजबूत आधार मानती है।

मुख्यमंत्री जी ने लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए एम0एस0एम0ई0 सेक्टर में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत सुझाव देने की बात कही। उन्होंने पैकेजिंग, डिजाइनिंग और एक्सपोर्ट प्रमोशन को और मजबूत करने में उद्योग समूहों से सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स सेक्टर में महिलाओं की बड़ी भूमिका को रेखांकित करते हुए इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए अधिक अवसर सृजित करने हेतु ठोस और व्यावहारिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्यमंत्री जी ने राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों के अनुरूप समय पर इन्सेंटिव वितरण के लिए उद्यमियों को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि घोषित प्रोत्साहनपारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उद्योगों तक पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने खिलौना उद्योग की सम्भावनाओं की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि प्रदेश में खिलौना पार्क का विकास किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने औद्योगिक भूमि की लागत कम करने पर भी विशेष जोर दिया और कहा कि भूमि, लॉजिस्टिक्स और अनुमोदन से जुड़ी लागत को कम कर निवेश को और आकर्षक बनाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि एम0एस0एम0ई0 इकाइयों और नए उद्यमियों के लिए सुगम वातावरण तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है।

महत्वपूर्ण बैठक में एक विशेष प्रस्तुतिकरण के माध्यम से उद्यमियों को बीते लगभग 09 वर्षों में उत्तर प्रदेश की परिवर्तनकारी विकास यात्रा से अवगत कराया गया। प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि नीतिगत स्थिरता, व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और प्रशासनिक सुधारों के चलते उत्तर प्रदेश आज देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में शामिल हो चुका है।

बैठक में बताया गया कि देश के कुल एक्सप्रेस-वे नेटवर्क का लगभग 55 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और दादरी में दोनों कॉरिडोर का इंटरसेक्शन राज्य को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करता है।यह भी बताया गया कि प्रदेश में उद्योगों के लिए कनेक्टिविटी और सप्लाई चेन पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। प्रस्तुतिकरण में निर्यात क्षेत्र की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया गया कि वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश का मर्चेंडाइज निर्यात बढ़कर लगभग 1.86 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो बीते सात-आठ वर्षों में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, डिफेंस और एग्रो-प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में निर्यात की क्षमता लगातार बढ़ी है।

बैठक में औद्योगिक विस्तार के आंकड़े साझा करते हुए बताया गया कि वर्ष 2003 में प्रदेश में लगभग 8,980 फैक्ट्रियां पंजीकृत थीं, जो वर्तमान में बढ़कर करीब 27,000 तक पहुंच चुकी हैं। औद्योगिक निवेश अब महानगरों के साथ-साथ पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में भी तेजी से फैल रहा है।

बैठक में यह भी बताया गया कि चौथी ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की निवेश परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा चुका है। अब लगभग 06 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लिए जी0बी0सी0/5 आयोजित की जाने वाली है।

बैठक में नीतिगत सुधारों की जानकारी देते हुए बताया गया कि उत्तर प्रदेश को डिरेगुलेशन 1.0 में देश में पहला स्थान मिला है। भवन निर्माण उपविधि-2025, ऑटो-स्क्रूटनी प्रणाली, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और 40 से अधिक कानूनों में संशोधन कर लगभग 200 अनुपालनों को समाप्त किए जाने जैसे सुधारों से उद्योगों को बड़ी राहत मिली है।

शीघ्र प्रारम्भ होने जा रहे निवेश मित्र 3.0 के माध्यम से 40 से अधिक विभागों की सेवाओं को एकीकृत किया गया है, दस्तावेजों और प्रक्रियाओं में उल्लेखनीय कमी की गई है और रियल-टाइम ट्रैकिंग तथा डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। बैठक में औद्योगिक क्लस्टरों के उन्नयन की जानकारी देते हुए बताया गया कि अगले 02 वर्षों में लगभग 5,000 करोड़ रुपये के निवेश से 185 औद्योगिक क्लस्टरों को बेहतर बुनियादी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कों के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बैठक में राज्य के प्रमुख उद्योग एवं व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों की व्यापक सहभागिता रही। इनमें भारतीय उद्योग परिसंघ उत्तर प्रदेश, फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री उत्तर प्रदेश, पी0एच0डी0 चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, एसोसिएटेड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री ऑफ इण्डिया (एसोचैम), एसोसिएटेड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री ऑफ इण्डिया (एसोचैम) उत्तर प्रदेश, भारतीय उद्योग संघ, लघु उद्योग भारती, दलित इण्डियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, नैसकॉम तथा भारतीय रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन का परिसंघ शामिल रहे।

बैठक में मुख्यमंत्री जी ने बजट 2026-27 के सन्दर्भ में और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को और प्रभावी बनाने के लिए उद्यमियों तथा उद्योग संगठनों से व्यावहारिक सुझाव देने का आह्वान किया। उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रदेश की औद्योगिक नीतियों, निवेश माहौल और विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार और सुझाव साझा किए।

सभी बैंक विकासोन्मुख क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाएँ, नागरिकों को सरल और समयबद्ध सेवा प्रदान करें : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 01 फरवरी 2026 को यहां लखनऊ में राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (एस0एल0बी0सी0) की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री जी ने चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रदेश में कुल क्रेडिट डिपॉजिट (सी0डी0 रेशियो) को 62 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने सभी बैंक प्रतिनिधियों से उनके सी0डी0 रेशियो के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए सी0डी0 रेशियो बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास करने पर बल दिया।

बैठक में बताया गया कि दिसम्बर, 2025 तक उत्तर प्रदेश का कुल सी0डी0 रेशियो 60.39 प्रतिशत हो गया है, जो पिछले लगभग दस वर्षों का सर्वाधिक स्तर है। जनपदवार समीक्षा के अनुसार 40 प्रतिशत से कम सी0डी0 रेशियो वाले जनपद घटकर केवल पाँच रह गए हैं, जबकि 40-50, 50-60 और 60-80 प्रतिशत की श्रेणी वाले जनपदों की संख्या में भी निरंतर सुधार हुआ है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक जनपद-एक उत्पाद (ओ0डी0ओ0पी0) की सफलता के बाद अब राज्य सरकार एक जनपद-एक व्यंजन (ओ0डी0ओ0सी0) के माध्यम से छोटे व्यापारियों, पारम्परिक पाक कला से जुड़े कारीगरों और गिग वर्कर्स को नई पहचान देने जा रही है। उन्होंने बैंकों से आह्वान किया कि जैसे ओ0डी0ओ0पी0 को वित्तीय सहयोग मिला, वैसे ही ओ0डी0ओ0सी0 को भी प्राथमिकता देते हुए अधिक से अधिक लोगों को ऋण उपलब्ध कराया जाए। सरकार प्रशिक्षण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में पूरा सहयोग दे रही है। इस मिशन को गति देने में बैंकों की भूमिका निर्णायक होगी।

मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का उदाहरण देते हुए कहा कि इन योजनाओं की सफलता के केंद्र में बैंकों की सहयोगी भावना है। अनावश्यक दस्तावेज़ों की मांग, बार-बार वेरिफिकेशन और प्रक्रिया में देरी जैसी स्थितियाँ लाभार्थियों को हतोत्साहित करती हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि बैंकिंग प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिससे आम नागरिक को वास्तविक सहूलियत मिले और पात्र लाभार्थी बिना किसी परेशानी के योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज आर्थिक गतिविधियों, औद्योगिक निवेश, उद्यमिता, कृषि और महिला-युवा स्वावलम्बन के क्षेत्रों में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस प्रगति में बैंकिंग तंत्र की सक्रिय साझेदारी अनिवार्य है। किसान, एम0एस0एम0ई0, स्टार्टअप, महिला स्वयं सहायता समूहों और नवउद्यमी युवाओं को ऋण उपलब्धता सरल, सम्मानजनक और समयबद्ध हो।

मुख्यमंत्री जी ने उन जनपदों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए जहाँ सी0डी0 रेशियो 40 प्रतिशत से कम है। बैंकों को गांवों को लक्षित कर मेगा ऋण मेले आयोजित करने चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने हर माह जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव को निर्देशित किया। उन्होंने बैंकों से सी0एस0आर0 के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास में सहभागी बनने का भी आह्वान किया।

बैठक में बताया गया कि विगत 08 वर्षों में प्रदेश का बैंकिंग तंत्र अत्यंत मजबूत हुआ है। मार्च, 2017 में प्रदेश की कुल जमा राशि 8.92 लाख करोड़ रुपये थी, जो दिसम्बर, 2025 में बढ़कर 20.44 लाख करोड़ रुपये हो गई है। इसी अवधि में कुल ऋण वितरण 4.05 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 12.34 लाख करोड़ रुपये पर पहुँच गया। मार्च, 2017 में प्रदेश का कुल बैंकिंग व्यवसाय 12.80 लाख करोड़ रुपये था, जो दिसम्बर, 2025 में बढ़कर 32.79 लाख करोड़ रुपये हो गया है। अप्रैल, 2022 से दिसम्बर, 2025 के दौरान अकेले जमा में 6.47 लाख करोड़ रुपये, ऋण में 5.03 लाख करोड़ रुपये और कुल बैंकिंग व्यवसाय में 11.50 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि, एम0एस0एम0ई0 और प्राथमिकता क्षेत्रों में ऋण प्रवाह लगातार बेहतर हुआ है। दिसम्बर, 2024 से दिसंबर, 2025 के बीच एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र में 23 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।

वित्तीय समावेशन अभियान (जुलाई-अक्टूबर, 2025) की उपलब्धियों की जानकारी भी बैठक में प्रस्तुत की गई। बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ऊर्जा, कृषि, बुनियादी ढाँचा, उद्योग, एम0एस0एम0ई0 और एन0बी0एफ0सी0 सह-ऋण मॉडल सहित विभिन्न क्षेत्रों में 22,000 करोड़ रुपये से अधिक के बड़े ऋण स्वीकृत किए गए हैं। यू0पी0पी0सी0एफ0, यू0पी0सी0यू0, पावर ट्रांसमिशन और अन्य औद्योगिक परियोजनाओं को भी महत्वपूर्ण स्वीकृतियाँ मिली हैं। विगत एक वर्ष में एम0एस0एम0ई0 दिवस, मुख्यमंत्री युवा कॉन्क्लेव, विश्वकर्मा जयंती, इण्टरनेशनल ट्रेड शो और उत्तर प्रदेश दिवस जैसे कार्यक्रमों में बड़े पैमाने पर ऋण वितरण किया गया।

योजनावार प्रगति प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 4.66 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 2.32 लाख को स्वीकृति और 2.07 लाख को ऋण वितरण किया गया। पी0एम0 स्वनिधि योजना में कुल 22.85 लाख आवेदनों के सापेक्ष 21.15 लाख को स्वीकृति और 20.72 लाख को ऋण वितरण किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2025 तक 50.82 लाख किसानों को 01 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सीमा स्वीकृत की गई। महिला स्वयंसहायता समूहों के बैंक-लिंकिंग में 2.16 लाख समूहों को सहायता प्रदत्त की गई।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसे और सशक्त बनाने में बैंकिंग तंत्र की सक्रियता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपेक्षा की कि सभी बैंक विकासोन्मुख क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाएँ, नागरिकों को सरल और समयबद्ध सेवा प्रदान करें और वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को जनपदवार पूरा करें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बैंक और सरकार मिलकर उत्तर प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति सुनिश्चित करेंगे।

केन्द्रीय बजट 2026-27 किसान, युवा, महिला और गरीब आदि की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 02 फरवरी, 2026 विजनरी केन्द्रीय बजट 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति आभार तथा केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा अपने सम्बोधन में कहा कि यह बजट किसान, युवा, महिला और गरीब आदि की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है। रिफॉर्म, ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन को एक सूत्र में पिरोकर मजबूत भारत के निर्माण की दिशा में यह बजट एक सुदृढ़ नींव के रूप में काम करेगा।

उन्होंने कहा कि यह बजट राष्ट्र और समाज के प्रति प्रत्येक भारतीय को अपने कर्तव्यों का बोध कराने का आग्रह कर रहा है। इसमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध और भविष्य की जिम्मेदारी दिखायी देती है। युवा शक्ति और समावेशी विकास को ध्यान में रखकर केन्द्रीय वित्त मंत्री ने संसद में यह बजट प्रस्तुत किया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में विगत 11 वर्षों में तय की गयी यात्रा की बदौलत नीतियों और योजनाओं का धरातल पर इम्पैक्ट दिखा है। परिणामस्वरूप विगत 11 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक की आबादी गरीबी रेखा से उबरकर आत्मगौरव के साथ देश की प्रगति में अपना योगदान दे रही है। जब नीति स्पष्ट तथा नीयत साफ होती है, तो परिणाम इसी रूप में सामने आते हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। यह प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव की बात है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस बजट से देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य की आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। प्रदेश के लिए नई सम्भावनाओं के द्वार खुले हैं। एम0एस0एम0ई0 सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का बजट प्राविधानित किया गया है। देश का सबसे बड़ा 96 लाख एम0एस0एम0ई0 यूनिट्स का बेस उत्तर प्रदेश के पास है। हमारी 03 करोड़ आबादी एम0एस0एम0ई0 के माध्यम से आर्थिक स्वावलम्बन के पथ पर अग्रसर है। एम0एस0एम0ई0 सेक्टर में 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' योजना को प्रमोट करते हुए उत्पादों को ब्राण्डिंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने का कार्य किया गया है। इससे निर्यात में वृद्धि तथा रोजगार का सृजन हुआ है।

बजट के अन्तर्गत यह 10,000 करोड़ रुपये हमें भविष्य के लिए नई तकनीक, ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक्सपोर्ट के साथ जुड़ने तथा पैकेजिंग की नई सम्भावनाओं को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को मदद करेंगे। इसका सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश ले पाएगा। 12 लाख 20 हजार करोड़ रुपये के इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड की घोषणा की गई है। इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा कनेक्टिविटी का विकास होगा। साथ ही, 07 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर घोषित हुए हैं। इसमें 02, दिल्ली-वाराणसी तथा वाराणसी-सिलीगुड़ी उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर रेल की स्पीड 300 से 500 किलोमीटर प्रति घण्टे होगी। इस स्पीड का लाभ प्रदेश को मिलेगा। बेहतरीन रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ ईस्टर्न एण्ड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, दोनों प्रदेश से होकर जा रहे हैं। लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा हब प्रदेश में तैयार हो रहा है। बजट में लॉजिस्टिक के लिए काफी संभावनाएं हैं। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में गौतमबुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी को डेवलप करने की कार्यवाही को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में देश का पहला इनलैंड वॉटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच प्रारम्भ हो चुका है। राज्य सरकार ने वाराणसी, प्रयागराज और यमुना नदी में भी वॉटर-वे को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार किए हैं। अयोध्या से हल्दिया के बीच वॉटर-वे को संचालित करने का भी प्रस्ताव है। इसी प्रकार, राप्ती तथा गोमती नदी में भी वॉटर-वे का उपयोग किया जा सकता है। इससे कार्गा मूवमेण्ट में बढ़ोत्तरी होगी। वाराणसी और पटना में शिप रिपेयर ईको-सिस्टम विकसित किये जाएंगे। इससे प्रदेश में इनलैण्ड वॉटर-वे की सुविधा तथा मूवमेण्ट को आगे बढ़ाने, कार्गो और ट्रांसपोर्टेशन की लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बायो-फार्मा सेक्टर में उत्तर प्रदेश में असीम सम्भावनाएँ हैं। जनपद ललितपुर में लगभग 1,200 एकड़ क्षेत्रफल में नये बल्क ड्रग पार्क के निर्माण की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा रहा है। जनपद गौतमबुद्धनगर के यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क की कार्यवाही एडवांस स्टेज में है। बायो-फार्मा के लिए 10,000 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है। यह भारत को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने में मदद करेगा। इस दिशा में उत्तर प्रदेश ने तेजी से अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाया है। इसके अन्तर्गत कल फार्मा से सम्बन्धित एक कॉन्क्लेव आयोजित होगी, जिसमें देशभर से इस फील्ड के स्टेक होल्डर लखनऊ में प्रतिभाग करेंगे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत को डाटा सेण्टर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में नए कदम बढ़ाए जा रहे हैं। प्रदेश में 22 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत के डाटा सेण्टर के निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 700 मेगावाट क्षमता के डाटा सेंटर स्थापित किए गए हैं। भारत सरकार ने डाटा सेंटर हब स्थापित करने के लिए जो धनराशि आरक्षित की है, इससे प्रदेश को सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना लॉन्च की गई है। देश में सबसे अधिक ग्राम पंचायतें तथा ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 01 लाख 05 हजार से अधिक राजस्व ग्राम हैं। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण उत्पादों को ग्लोबल मार्केटिंग नेटवर्क से जोड़ने में मदद मिलेगी। स्थानीय कारीगरों को अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। विकसित भारत जी-राम-जी योजना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर मार्केट विकसित करने में मदद मिलेगी।

उत्तर प्रदेश के ढाई लाख बुनकरों के ग्रामीण उद्योगां को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पी0एम0 विश्वकर्मा योजनाओं के माध्यम से प्रमोट किया गया है। अर्थात पूरा होमवर्क प्रदेश में पहले से हुआ है। स्वाभाविक रूप से महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का लाभ प्रदेश को प्राप्त होगा। इसके माध्यम से युवाओं को स्वावलम्बन की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी।

राज्य सरकार ने विगत 09 वर्ष में प्रदेश में महिला कार्यबल तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। आज प्रदेश में 12 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत महिला कार्यबल अलग-अलग सेक्टर में कार्य कर रही है। राज्य सरकार के बजट से कामकाजी महिलाओं के लिए 07 हॉस्टल प्रदेश को उपलब्ध हुए थे। शिक्षा में बराबरी की गारंटी के लिए इस केन्द्रीय बजट के माध्यम से छात्राओं के लिए हॉस्टल निर्माण की कार्यवाही को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश टूरिज्म के नए हब के रूप में उभरा है। कल ही माघ मेले का एक चरण सम्पन्न हुआ। राज्य सरकार की बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और सुविधा के परिणामस्वरूप करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगायी। पौष पूर्णिमा पर लगभग एक करोड़, मकर संक्रांति पर ढाई करोड़, मौनी अमावस्या पर चार करोड़, बसंत पंचमी पर तीन करोड़ से अधिक तथा माघी पूर्णिमा पर 02 करोड़ 10 लाख से अधिक कल्पवासियों और पूज्य संतों ने प्रयागराज त्रिवेणी में स्नान किया। अर्थात गवर्नमेण्ट यदि थोड़ा भी फैसिलिटेट करे और सुविधा व सुरक्षा की उचित व्यवस्था करे तो वह स्थान एक बेहतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन केन्द्र के रूप में स्थापित हो सकता है। प्रयागराज, काशी, अयोध्या, मथुरा, वृन्दावन, माँ विन्ध्यवासिनी धाम और बौद्ध परिपथ इसके उदाहरण हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बजट में 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को डेवलप करने का प्राविधान किया गया है, जिसमें 02-सारनाथ (वाराणसी) और हस्तिनापुर, मेरठ की महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट्स सम्मिलित हैं। इसके अलावा, अन्य पौराणिक एवं ऐतिहासिक साइट्स को भी इसी तर्ज पर विकसित करने में सहायता मिलेगी। इससे टूरिज्म को और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश में टूरिस्ट गाइड को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। 10,000 टूरिस्ट गाइड्स के प्रशिक्षण और उन्हें स्किल अप करने की दिशा में कार्य प्रारम्भ किये जाएंगे। प्रदेश में कई पर्यटन केन्द्र तैयार किए गए हैं। इसके माध्यम से युवाओं को व्यापक पैमाने पर रोजगार प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभर रहे हैं। केन्द्रीय बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने सेमीकंडक्टर पार्क की जो घोषणा की है, इसका लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा। इससे सम्बन्धित प्रदेश को कई अहम प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में बेहतरीन कार्य हुए हैं। देश के कुल प्रोडक्शन का 55 प्रतिशत प्रदेश में मैन्युफैक्चर हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेण्ट की 60 प्रतिशत मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश कर रहा है, जो लगभग 02 लाख करोड़ रुपये की है। उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में नए रूप में केन्द्र सरकार की इस योजना का लाभ लेने में सफल होगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बजट में 05 लाख की आबादी के शहरों में खास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए घोषणा की गई है। प्रदेश की 762 अर्बन बॉडीज में से 225 अर्बन बॉडीज की आबादी 05 लाख या उससे अधिक है। इसके अन्तर्गत 17 नगर निगम तथा शेष नगर पालिका परिषदें हैं। स्वाभाविक रूप से इस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ प्रदेश के शहरों को प्राप्त होगा। इसके माध्यम से शहरों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत 09 वर्षों में डबल इंजन सरकार द्वारा हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर में किये गये कार्यों का लाभ प्रदेश के नागरिक प्राप्त कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की क्षमता विस्तार की मांग की जाती थी। हमें प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की क्षमता को दोगुना करना है। प्रदेश में 'वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास 98 डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल हैं, जिनकी क्षमता बढ़ाने के लिए प्राप्त सहयोग से स्थानीय स्तर पर लोगों को काफी सुविधा होगी। अक्सर ट्रॉमा सेण्टर के अभाव में गोल्डन आवर में काफी लोगों की जान चली जाती है। इस बजट के माध्यम से हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने तथा सभी जनपदों में इमरजेन्सी और ट्रॉमा सेण्टर खोलने की सुविधा प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बजट में 03 नए ऑल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना की घोषणा की गई है। राज्य सरकार पहले ही वाराणसी में ऑल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना के लिए अनुरोध कर चुकी है। भगवान धनवन्तरी की जन्मस्थली काशी से इसे आगे बढ़ाने के साथ-साथ प्रदेश को हेल्थ टूरिज्म केन्द्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। प्रदेश को मेडिकल टूरिज्म और एलाइड हेल्थ के माध्यम से मेडिकल हब के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बजट में 'समर्थ' नाम से एक नई योजना शुरू की गई है, जिसके माध्यम से खेल उद्योग तथा खेल सामग्री के मैन्युफैक्चरिंग सेण्टरों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 'समर्थ' योजना के माध्यम से प्रदेश को स्पोर्ट्स आइटम के एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स प्रोडक्ट के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा।

उत्तर प्रदेश में 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' योजना के अन्तर्गत मेरठ को खेल सामग्री के मैन्युफैक्चरिंग केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है। आगरा और कानपुर के लेदर क्लस्टर में भी स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मेरठ का कार्य आगामी अप्रैल-मई तक पूरा हो जाएगा। प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्राइवेट एकेडमी को प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाए गये हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत विस्तार या कृषि प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान को उसकी भाषा में कृषि के बारे में अवगत कराया जा सकेगा। इससे कृषि सम्बन्धी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। शी-मार्ट (सेल्फ हेल्प आन्त्रेप्रेन्योर मार्ट) योजना का सीधा लाभ महिला स्वयंसेवी समूह की लखपति दीदियों को प्राप्त होगा। इसके माध्यम से महिला स्वयंसेवी समूह के प्रोडक्ट्स का नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, केन्द्रीय करों में सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश का है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज सड़क के साथ स्पीड, निवेश के साथ विश्वास, पहचान के साथ आत्मगौरव का भाव भी है। शासन के साथ-साथ निर्णायक नेतृत्व भी है। इन्फ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेस-वे, रेलवे कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर, लॉजिस्टिक, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि के लिए बजट में की गई घोषणाओं का लाभ प्रदेश को प्राप्त होगा। लाखों युवाओं को रोजगार की सुविधा मिलेगी, जो प्रदेश की युवा शक्ति को प्रदेश में ही उनकी प्रतिभा का लाभ प्रदान करने में मददगार सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए प्रदेश में 06 नोड्स विकसित किये जा रहे हैं। यहाँ लगभग 12,500 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें काफी प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। अलग-अलग नोड्स में 400 युवाओं को रोजगार मिला है। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की कार्यवाही भी चल रही है। ब्रह्मोस मिसाइल के मैन्युफैक्चरिंग कार्य को आगे बढ़ाने के लिए लखनऊ में पी0टी0सी0 जैसी यूनिट लग चुकी हैं। अडानी एम्युनेशन का कार्य कानपुर में युद्धस्तर पर आगे बढ़ चुका है। भारत डायनमिक्स लिमिटेड की कार्यवाही झाँसी में अन्तिम स्टेज पर है। डिफेन्स क्षेत्र में बढ़े हुए बजट का लाभ उत्तर प्रदेश को डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग के नए हब के रूप में स्थापित करने में सहायक होगा तथा इसका लाभ यहाँ के निवेशकों को प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसी बजट के आधार पर इस माह में उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। डबल इंजन सरकार के इस बजट का लाभ देश की सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा और प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत@2047 के संकल्पों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 30 जनवरी 2026 को लखनऊ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

ऐसी बीज नीति तैयार की जाए, जो आने वाले वर्षों की कृषि चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करे : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 02 फरवरी, 2026 को यहां लखनऊ में आयोजित एक बैठक में 'उत्तर प्रदेश बीज नीति-2026' के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कृषि उत्पादन की वास्तविक शक्ति उच्च गुणवत्तायुक्त, भरोसेमंद और प्रमाणित बीजों में निहित है। प्रदेश के लिए नई और आधुनिक 'बीज नीति' समय की मांग है। भूमि जोत लगातार घट रही है, ऐसे में ध्यान केवल रकबे पर नहीं, बल्कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने पर होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि उच्च उपज, रोग-प्रतिरोधी और जलवायु-सहिष्णु किस्मों के विकास को प्राथमिकता देते हुए ऐसी बीज नीति तैयार की जाए, जो आने वाले वर्षों की कृषि चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करे।

मुख्यमंत्री जी ने आगामी 05 वर्षों के लिए प्रदेश की बीज उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता और उपलब्धता को नए स्तर तक ले जाने के लिए ठोस रोडमैप तैयार करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बीज उत्पादन, प्रसंस्करण और भण्डारण की पूरी प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग आवश्यक है, ताकि प्रमाणित बीज की कमी न हो और किसान सशक्त बन सकें।

मुख्यमंत्री जी ने भरोसेमंद बीज आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बीज की एण्ड-टू-एण्ड ट्रेसेबिलिटी को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों तक पहुँचने वाला बीज पैकेट प्रमाणित, परीक्षणित और पूरी तरह से मानकयुक्त होना चाहिए। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालयों, आई0सी0ए0आर0 संस्थानों, उपकार तथा निजी बीज उद्योग को एक साझा मंच पर लाकर बीज अनुसन्धान, नवाचार और किस्म-रिलीज प्रक्रिया को तेज़ करने की आवश्यकता बताई।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फसल विविधीकरण को गति देने के लिए दलहन, तिलहन, मक्का, बाजरा, ज्वार और बागवानी फसलों के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता हेतु विशेष रणनीति तैयार की जाए। उन्होंने प्रदेश में आगामी 05 वर्षों में कम से कम 05 'सीड पार्क' स्थापित करने की दिशा में तेजी से काम करने के निर्देश दिए। ये सीड पार्क उत्पादन, प्रसंस्करण, गुणवत्ता परीक्षण और भण्डारण की सभी सुविधाओं से सुसज्जित एकीकृत परिसर होंगे।

मुख्यमंत्री जी कहा कि प्रदेश के सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों को बीज विकास कार्यक्रम से सीधे जोड़ा जाए, ताकि अनुसंधान, प्रशिक्षण और खेत-स्तर पर तकनीक के प्रसार के बीच सुदृढ़ समन्वय स्थापित हो सके। प्रदेश के 09 क्लाइमेटिक जोन के अनुरूप एक-एक कृषि विज्ञान केन्द्र को सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाए, जिससे क्षेत्र-विशेष की फसलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज और तकनीकी समाधान तैयार किए जा सकें। मुख्यमंत्री जी ने प्रगतिशील किसानों को भी बीज विकास कार्यक्रमों से जोड़ने पर बल दिया, ताकि स्थानीय अनुभव और आधुनिक तकनीक का प्रभावी समन्वय बन सके।

मुख्यमंत्री जी ने कृषि में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि अधिकाधिक ट्यूबवेलों को सौर ऊर्जीकरण से जोड़ा जाए, जिससे किसानों का सिंचाई खर्च कम हो और कृषि में स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़े। उन्होंने प्रदेश में स्थापित सोलर पैनल इकाइयों को प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए कहा कि स्थानीय निर्माण को बढ़ावा मिलने से रोजगार, निवेश और कृषि अवसंरचना को मजबूती मिलेगी।

'गन्ना आधारित अंतः फसली खेती' उत्तर प्रदेश के कृषि भविष्य का नया मॉडल : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 02 फरवरी, 2026 को यहां लखनऊ में आयोजित एक बैठक में गन्ना के साथ तिलहनी एवं दलहनी अन्तःफसली खेती के प्रोत्साहन की योजना के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा किप्रदेश में कृषि योग्य भूमि का क्षैतिज विस्तार अब सम्भव नहीं है, इसलिए एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य के लिए उत्पादन बढ़ाने का एकमात्र रास्ता इकाई क्षेत्रफल से अधिक फसल उत्पादन है। उन्होंने कहा कि 'गन्ना आधारित अन्तःफसली खेती' उत्तर प्रदेश के कृषि भविष्य का नया मॉडल है। यह किसानों को अधिक उत्पादन, अधिक कमाई और जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री जी कहा कि गन्ना के साथ तिलहनी एवं दलहनी अन्तःफसली खेती के प्रोत्साहन की योजना को वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक मिशन अतिरिक्त उत्पादन, कम लागत के साथ पूरे वर्ष स्थिर आय उपलब्ध कराती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। मोड में लागू किया जाए। वर्तमान में प्रदेश में 29.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती होती है, जिसमें 14.64 लाख हेक्टेयर नया बोया गया क्षेत्र और 14.86 लाख हेक्टेयर पेड़ी शामिल है। इतने बड़े क्षेत्र में तिलहन और दलहन की अन्तःफसल जोड़ने से उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और प्रदेश एवं देश को तिलहन-दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को नई मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की नई छलांग का सबसे प्रभावी तरीका 'गन्ना के साथ तिलहनी एवं दलहनी अन्तःफसली खेती' को बड़े पैमाने पर लागू करना है। यह मॉडल गन्ना किसानों की आय को दोगुना ही नहीं, बल्कि 'बहु-गुणित' करने की क्षमता रखता है। गन्ने के साथ सरसों, मसूर, उर्द और मूंग जैसी उच्च मूल्य वाली अन्तःफसल किसानों को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कृषि विज्ञान केन्द्र एवं कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से क्रियान्वित करते हुए अन्तःफसल का चयन वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक आधार पर किया जाए। उन्होंने आई0सी0ए0आर0 की सिफारिशों के अनुसार, रबी सीजन में सरसों और मसूर तथा जायद सीजन में उर्द और मूंग को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गन्ने की पैदावार प्रभावित किए बिना अतिरिक्त फसल, अतिरिक्त लाभ और अतिरिक्त सुरक्षा इस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत है। इस योजना के लिए वर्षवार रोडमैप तैयार किया जाए। यह अतिरिक्त उत्पादन सीधे किसानों की आय में वृद्धि करेगा और राज्य के जी0वी0ए0 में बड़ा योगदान देगा। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सहायता और अनुदान का ढांचा स्पष्ट होना चाहिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बड़े पैमाने पर अन्तःफसलों को अपनाने से किसानों को तेज़ नकदी प्रवाह मिलेगा और एकल फसल जोखिम कम होगा, जिससे कृषि और अधिक स्थिर और टिकाऊ बनेगी। यह योजना केवल गन्ना क्षेत्र से जुड़े किसानों के लाभ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे प्रदेश के व्यापक कृषि परिदृश्य के परिवर्तन के रूप में लागू किया जाना चाहिए।

'सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेण्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन' प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और उद्यमिता का एक सशक्त केंद्र बनेगा : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 02 फरवरी, 2026 को यहां लखनऊ में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में औद्योगिक विकास को रोजगार से सीधे जोड़ने के उद्देश्य से सभी जनपदों में 'सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेण्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन' विकसित करने के लिए उपयुक्त भूमि शीघ्र चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति का लक्ष्य ऐसा सक्षम वातावरण तैयार करना है, जहाँ युवाओं को कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता के अवसर एक ही परिसर में सुलभ हों। उन्होंने निर्देश दिए कि इस महत्वाकांक्षी योजना को स्थानीय आवश्यकताओं और क्षेत्रीय सम्भावनाओं के अनुरूप प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस पर शुभारम्भ की गयी यह योजना उद्योग, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार तथा उद्योग-सहायता से जुड़े विभागों और सुविधाओं को एकीकृत रूप से उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने एम0एस0एम0ई0, सेवा आधारित उद्योगों और नवाचार से जुड़े क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए प्लग-एण्ड-प्ले यूनिट और फ्लैटेड फैक्ट्री जैसी आधुनिक सुविधाओं के विकास पर विशेष बल दिया, जिससे उद्यमियों को प्रारम्भ से ही आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध हो सके।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 'सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेण्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन' प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और उद्यमिता का एक सशक्त केन्द्र बनेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सम्भावित स्थलों की शीघ्र पहचान कर परियोजना के क्रियान्वयन को गति दी जाए, ताकि यह पहल प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन का एक प्रभावी मॉडल बन सके।

बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि इस योजना के अंतर्गत कॉमन फैसिलिटी सेंटर, टेस्टिंग फैसिलिटी, डिस्प्ले एवं डिजाइन सेंटर, टूल रूम, ई0टी0पी0/सी0ई0टी0पी0, प्लग-एण्ड-प्ले यूनिट तथा फ्लैटेड फैक्ट्री की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही, युवाओं के कौशल उन्नयन हेतु उद्यमिता प्रशिक्षण, मेन्टरिंग, विभिन्न ऋण योजनाओं की जानकारी तथा हैण्ड-होल्डिंग की व्यवस्था भी इसी परिसर से की जाएगी। योजना को चरणबद्ध रूप से प्रदेश के सभी जनपदों में लागू किए जाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक जनपद में न्यूनतम 50 एकड़ क्षेत्रफल में एम्प्लॉयमेण्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन विकसित किए जाएंगे।

प्रस्तावित जोन के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र, फ्लैटेड फैक्ट्री, वाणिज्यिक क्षेत्र, सड़क, कॉमन फैसिलिटी, सर्विस सेक्टर, ग्रीन एरिया और कार्यालय स्पेस का संतुलित ले-आउट तैयार किया गया है। साथ ही, 'सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेण्ट एण्ड स्किल डेवलपमेण्ट सेण्टर' की स्थापना भी प्रस्तावित है, जिसमें प्रशिक्षण हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम, एक्सटेंशन काउण्टर और उद्योग-सहायता से जुड़ी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि ऑपरेशनल मॉडल के अन्तर्गत स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रशिक्षण, कौशल विकास, इण्टर्नशिप, अप्रेण्टिसशिप तथा सम्बन्धित उद्योगों में वेतन आधारित रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

सीता माता के उज्ज्वल चरित्र से नई पीढ़ी को परिचित कराना समय की आवश्यकता:मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 04 फरवरी, 2026 को यहां लखनऊ में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री अयोध्या धाम में माता सीता के जीवन-चरित पर केन्द्रित 'वैदेही आर्ट गैलरी' की स्थापना के निर्देश दिए। उन्होंने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि सीता माता भारतीय संस्कृति, मर्यादा और नैतिक आदर्शों की अनुपम प्रेरणा हैं। उनके उज्ज्वल चरित्र से नई पीढ़ी को गहराई से परिचित कराना समय की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री जी ने आर्ट गैलरी की परिकल्पना साझा करते हुए कहा कि यह अत्याधुनिक गैलरी केवल एक कला-संग्रहालय न होकर, सीता माता के जीवन, त्याग, करुणा, मर्यादा, धैर्य और शक्ति का आधुनिक तकनीक के माध्यम से पुनर्पाठ प्रस्तुत करने वाली एक जीवन्त सांस्कृतिक अनुभव-स्थली होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस गैलरी की कथा-वस्तु, डिजाइन, विज़ुअल भाषा, कला और तकनीक सहित सभी आयाम इस भावना को प्रकट करें कि हम एक दिव्य विरासत का पुनर्पाठ कर रहे हैं, जिसे नई पीढ़ी के सामने प्रेरणास्रोत के रूप में स्थापित किया जाना है। वैदेही आर्ट गैलरी की मूल भावना यही हो कि आगन्तुक सीता माता के जीवन-सन्देश को केवल देखें ही नहीं, बल्कि उसका अनुभव करें, समझें और आत्मसात करें।

अयोध्या विकास प्राधिकरण के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह परियोजना अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निकट वशिष्ठ भवन परिसर में विकसित की जा सकती है, जहां प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस गैलरी का विकास अयोध्या के वैश्विक सांस्कृतिक नगर के रूप में उभरने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण चरण होगा। इस गैलरी में मिथिला की संस्कृति, लोक परम्परा और कला के विविध आयामों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए।

प्रदेश में फार्मा सेक्टर के लिए बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर,सबसे बड़ा कन्ज्यूमर मार्केट और वर्कफोर्स उपलब्ध : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 03फरवरी, 2026 को यहां वैश्विक निवेशकों एवं उद्यमियों के महासंगम 'उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0' के शुभारम्भ अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में फार्मा सेक्टर के लिए बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़ा कन्ज्यूमर मार्केट और वर्कफोर्स उपलब्ध है। प्रदेश सरकार अपने प्रत्येक निवेशक को 'ट्रिपल एस' अर्थात् 'सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड' की गारण्टी उपलब्ध कराती है। आज उत्तर प्रदेश ट्रस्ट, ट्रान्सफॉर्मेशन और टाइमली डिलीवरी के रोल मॉडल के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने तथा प्रदेश को फार्मा सेक्टर में अग्रणी मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री जी के समक्ष औषधि, चिकित्सा उपकरण एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में 5,525 करोड़ रुपए के 11 एम0ओ0यू0 का आदान-प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार ने फार्मा के क्षेत्र में अनेक सम्भावनाओं को प्रदेश में आगे बढ़ाया गया है।ललितपुर प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध जनपद है। प्रदेश के पहले फार्मा पार्क के लिए ललितपुर में भूमि अधिग्रहीत की गई। उसे विकसित कर भूमि आवण्टन की कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के कर-कमलों से देश के सबसे बड़े जेवर इण्टरनेशनल एयरपोर्ट को इसी माह राष्ट्र को समर्पित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी से सटे हुए लगभग 350 एकड़ क्षेत्रफल में मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया है। इसे तेजी के साथ विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में स्थापित मेडिकल डिवाइस पार्क में अब तक 100 से अधिक फार्मा कम्पनियां जुड़ चुकी हैं। यहां पर यू0एस0एफ0डी0ए0 टेस्टिंग लैब स्थापित करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। जनपद ललितपुर के फार्मा पार्क को हब एण्ड स्पोक मॉडल के रूप में विकसित करते हुए आर0 एण्ड डी0 की बेहतरीन फैसिलिटी उपलब्ध करायी जाएगी। सरकार लखनऊ में एक वर्ल्ड क्लास फार्मा इन्स्टीट्यूट के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है। गौतमबुद्धनगर, बरेली तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी फार्मा पार्क को विकसित करने का कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस नीति के अन्तर्गत सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी, आर0 एण्ड डी0 तथा एक्सपोर्ट में बेहतरीन इन्सेन्टिव की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश में एफ0डी0आई0 एण्ड फॉर्च्यून-500 पॉलिसी के अन्तर्गत एफ0डी0आई0 को आमंत्रित करने का बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज राज्य सरकार के पास लैण्ड बैंक है। बेहतरीन सुरक्षा तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधा है। प्लग एंड प्ले के लिए सरकार ने अधिकारियों को उद्यमियों को सस्ती भूमि उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया है। रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट की अच्छी सुविधा का विकास करने के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता है, राज्य सरकार लगाएगी। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं, बल्कि देश की इकोनॉमी का ब्रेक-थ्रू स्टेट बन कर उभरा है। उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस राज्य के रूप में कार्य कर रहा है। हमें प्रदेश में ऐसा इकोसिस्टम बनाना है, जहां विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में मिलकर कार्य करने के बेहतर परिणाम सामने आएंगे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में अनेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मौजूद हैं। आई0आई0टी0 कानपुर के सहयोग से 1,200 करोड़ रुपये की लागत से मेड-टेक का सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स विकसित किया जा रहा है। इसमें राज्य सरकार तथा आई0आई0टी0 कानपुर के पूर्व छात्र सहयोग कर रहे हैं। प्रदेश में दूसरे सेण्टर के रूप में एस0जी0पी0जी0आई0 विकसित हो रहा है। लखनऊ में सी0डी0आर0आई0 व एन0बी0आर0आई0 जैसे राष्ट्रीय स्तर की चार केन्द्रीय लैबोरेट्रीज स्थित हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में अब सरकारी योजनाओं में 'पिक एंड चूज' तथा पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति नहीं है। प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित 34 सेक्टोरियल पॉलिसीज मौजूद हैं। सभी निवेशकों को सिंगल विण्डो प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। निवेशकों को पॉलिसी के दायरे में रहकर समय पर इन्सेन्टिव दिया जा रहा है। प्रत्येक स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग तथा जवाबदेही तय की जाती है। बेहतर कनेक्टिविटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा निवेश का अच्छा माहौल देने के साथ ही, प्रदेश देश के उन बड़े राज्यों में से एक है, जिन्होंने अपना फॉरेस्ट कवर भी बढ़ाया है। भौतिक विकास के साथ ही पर्यावरण पर भी ध्यान देते हुए प्रदेश सरकार ने विगत 09 वर्षों में अपने फॉरेस्ट कवर को भी तेजी के साथ विकसित किया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज, निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज की तुलना में कम थे। अस्पतालों की स्थिति बहुत दयनीय थी। हमारी सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित राज्य के 38 जनपदों में जापानी इन्सेफेलाइटिस जैसी बीमारी को पूरी तरह समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है। यह कार्य सरकार की साफ नीयत तथा स्पष्ट नीतियों से सम्भव हुए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 03फरवरी, 2026 को यहां वैश्विक निवेशकों एवं उद्यमियों के महासंगम 'उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0' के शुभारम्भ अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में फार्मा सेक्टर के लिए बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़ा कन्ज्यूमर मार्केट और वर्कफोर्स उपलब्ध है। प्रदेश सरकार अपने प्रत्येक निवेशक को 'ट्रिपल एस' अर्थात् 'सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड' की गारण्टी उपलब्ध कराती है। आज उत्तर प्रदेश ट्रस्ट, ट्रान्सफॉर्मेशन और टाइमली डिलीवरी के रोल मॉडल के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने तथा प्रदेश को फार्मा सेक्टर में अग्रणी मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री जी के समक्ष औषधि, चिकित्सा उपकरण एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में 5,525 करोड़

रुपए के 11 एम0ओ0यू0 का आदान-प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार ने फार्मा के क्षेत्र में अनेक सम्भावनाओं को प्रदेश में आगे बढ़ाया गया है।ललितपुर प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध जनपद है। प्रदेश के पहले फार्मा पार्क के लिए ललितपुर में भूमि अधिग्रहीत की गई। उसे विकसित कर भूमि आवण्टन की कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के कर-कमलों से देश के सबसे बड़े जेवर इण्टरनेशनल एयरपोर्ट को इसी माह राष्ट्र को समर्पित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी से सटे हुए लगभग 350 एकड़ क्षेत्रफल में मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया है। इसे तेजी के साथ विकसित किया जा रहा है। नोएडा व ग्रेटर नोएडा जैसे प्राधिकरणों में विगत 46 वर्षों में 34,000 एकड़ का लैण्ड बैंक विकसित किया गया, जबकि अकेले बीडा को 56,000 एकड़ लैण्ड में विकसित किया जा रहा है। अगले 02 वर्षों में वहां निवेश प्रारम्भ हो जाएंगे। यहां भूमि आवण्टन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। हम यहां एयरपोर्ट, बेहतर कनेक्टिविटी, जल संसाधन, अच्छा लॉजिस्टिक व अन्य सुविधाएं देने जा रहे हैं। कच्चे माल के स्रोत, सप्लाई चेन मार्केट, वैल्यू चेन के साथ पर्याप्त स्किल यहां पर मौजूद है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज प्रदेश में स्किल, साइंस और स्टार्टअप्स की त्रिवेणी है। आज प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है। कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं है। देश में डी-रेगुलेशन रैंकिंग में प्रदेश प्रथम स्थान पर है। 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में देश का टॉप अचीवर स्टेट है। डी-क्रिमिनलाइजेशन के माध्यम से सरकार ने 13 एक्ट के आपराधिक प्राविधानों को समाप्त कर इंडस्ट्री को बेखौफ होकर कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। एम0एस0एम0ई0 सेक्टर में निवेशकों को 1,000 दिन तक किसी भी प्रकार की एन0ओ0सी0 से मुक्त किया गया है। अन्य सेक्टरों में भी निवेश नियमों का सरलीकरण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश में कुल 14,000 कारखाने संचालित थे। विगत 09 वर्षों में डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड के कारण इनकी संख्या बढ़कर 30,000 से अधिक हो गयी है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एम0एस0एम0ई0 सेक्टर में 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' योजना के माध्यम से प्रदेश के लोकल उत्पाद को ग्लोबल बनाया जा रहा है। देश की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55 प्रतिशत और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60 प्रतिशत प्रोडक्शन प्रदेश में हो रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 29 जनवरी, 2026 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

अमृत-2.0 योजना के अंतर्गत नगर निगम, गोरखपुर में सीवरेज योजना जोन-ए-3 से सम्बन्धित परियोजना तथा व्यय-वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत 72140.41 लाख रु0 का व्यय प्रस्ताव अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन-2.0 (अमृत-2.0) योजना के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर के नगर निगम, गोरखपुर में सीवरेज योजना जोन-ए-3 से सम्बन्धित परियोजना तथा व्यय-वित्त समिति द्वारा उसकी अनुमोदित लागत 72140.41 लाख रुपये (जी0एस0टी0 एवं सेंटेज सहित) का व्यय प्रस्ताव अनुमोदित किया है।

अमृत-2.0 योजना के अन्तर्गत नगर निगम, वाराणसी में दुर्गाकुंड, नरिया सराय नंदन, जोल्हा उत्तरी एवं भेलूपुर वार्ड में सीवर लाइन बिछाने एवं गृह संयोजन कार्य सम्बन्धी परियोजना की लागत 26649.44 लाख रु0 का व्यय प्रस्ताव अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन-2.0 (अमृत-2.0) योजना के अन्तर्गत जनपद वाराणसी के नगर निगम, वाराणसी में दुर्गाकुंड, नरिया सराय नंदन, जोल्हा उत्तरी एवं भेलूपुर वार्ड में सीवर लाइन बिछाने एवं गृह संयोजन कार्य से सम्बन्धित परियोजना की व्यय-वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत 26649.44 लाख रुपये (जी0एस0टी0 एवं सेंटेज सहित) का व्यय प्रस्ताव अनुमोदित किया है।

'उ0प्र0 शहरी पुनर्विकास नीति-2026' स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने 'उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति-2026' को लागू कराये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। नीति के प्राविधान मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरांत शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी होंगे। नीति को लागू किये जाने से राज्य सरकार पर कोई व्यय भार नहीं आयेगा। इस नीति में भविष्य में किसी प्रकार के संशोधन/परिवर्धन एवं नीति के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये वित्तपोषण के रूप में विकास शुल्क की संशोधित प्रणाली लागू करने तथा उ0प्र0 नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2014 (यथा संशोधित 2021) में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये वित्तपोषण के रूप में विकास शुल्क की संशोधित प्रणाली लागू किये जाने तथा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2014 (यथा संशोधित 2021) में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

बरेली में विज्ञान पार्क एवं नक्षत्रशाला का निर्माण किये जाने हेतु बरेली विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने जनपद बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा रामगंगा नगर आवासीय योजना, सेक्टर-8 में चिन्हित 5.33 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित मैराइन पार्क, स्पेस पार्क तथा ए0आई0 पार्क के साथ इसी चिन्हित भूमि में से 3,000 वर्गमीटर की भूमि पर विज्ञान पार्क एवं नक्षत्रशाला का निर्माण किये जाने हेतु बरेली विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

मुरादाबाद में विज्ञान पार्क व नक्षत्रशाला के निर्माण हेतु मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यदायी संस्था नामित

मंत्रिपरिषद ने जनपद मुरादाबाद में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली-बरेली मार्ग पर विकसित की जाने वाली गोविन्दपुरम् आवासीय योजना के अन्तर्गत 4.6 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित सेण्ट्रल पार्क में विज्ञान पार्क एवं नक्षत्रशाला का निर्माण किये जाने हेतु मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल लि0 मोरना, मुजफ्फरनगर की पेराई क्षमता विस्तार, तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण करते हुये नयी चीनी मिल की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल लि0 मोरना, जनपद मुजफ्फरनगर की पेराई क्षमता विस्तार, तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण करते हुये नयी चीनी मिल की स्थापना किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल लि0, लखनऊ की अधीनस्थ दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल, मोरना की पेराई क्षमता 2,500 टी0सी0डी0 से बढ़ाकर 3,500 टी0सी0डी0 (प्रथम चरण में 3,500 टी0सी0डी0 तत्पश्चात विस्तारित क्षमता 5,000 टी0सी0डी0) करते हुए नई चीनी मिल की स्थापना की जाएगी।

जनपद लखनऊ-हरदोई में प्रस्तावित पी0एम0 मित्र टेक्सटाइल पार्क हेतु जलापूर्ति परियोजना की लागत 45850.11 लाख रु0 का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने जनपद लखनऊ-हरदोई में प्रस्तावित पी0एम0 मित्र टेक्सटाइल पार्क हेतु जलापूर्ति प्रायोजना की लागत 45850.11 लाख रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।निर्णय के अनुसार प्रस्तावित पी0एम0 मित्र टेक्सटाइल पार्क में जलापूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा 16 एम0एल0डी0 टी0टी0पी0 के निर्माण, स्वच्छ जलापूर्ति (गोमती नदी से) के लिये 8.25 एम0एल0डी0 इन्टेकवेल एवं राइजिंग मेन तथा स्वच्छ जलापूर्ति (भू-गर्भ जल से) के लिये 4.50 एम0एल0डी0 ट्यूबवेल, पम्प हाउस एवं राइजिंग मेन से सम्बन्धित कार्यों को फेजवाइज़ आवश्यकतानुसार किया जाना है।

जनपद वाराणसी/चन्दौली में मोहनसराय उपाध्याय नगर चकिया मार्ग के 11.235 कि0मी0 लम्बाई में 04/06 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की पुनरीक्षित लागत 32593.08 लाख रु0 का व्यय प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने जनपद वाराणसी/चन्दौली में मोहनसराय उपाध्याय नगर चकिया मार्ग (राज्य मार्ग सं0-120) के चैनेज 21.000 से चैनेज 32.235 तक 04/06 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (लम्बाई 11.235 कि0मी0) कार्य की सम्पूर्ण परियोजना की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत 32593.08 लाख रुपये के व्यय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

जनपद देवरिया में देवरिया कसया मार्ग का 31.500 कि0मी0 लम्बाई में 4-लेन चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा 05 वर्षीय अनुरक्षण की लागत 29206.66 लाख रु0 का व्यय प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने जनपद देवरिया में देवरिया कसया मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-79) के चैनेज 1.600 से चैनेज 33.100 तक (लम्बाई 31.500 कि0मी0) 4-लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की सम्पूर्ण परियोजना तथा कार्य की 05 वर्षीय अनुरक्षण सहित व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत 29206.66 लाख रुपये (दो अरब बानवे करोड़ छः लाख छाछठ हजार रुपये) के व्यय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।इस मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हो जाने से देश-प्रदेश व विदेशों के श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को देवरिया शहर एवं भगवान बुद्ध की महा-परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, कुशीनगर अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा व नेपाल राष्ट्र आदि आने-जाने में सुगम यातायात की सुविधा प्राप्त होगी एवं जनपद तथा क्षेत्र का चहुंमुखी विकास होगा।

उप निबन्धक कार्यालय में वर्ष 2002 से 2017 तक के पंजीकृत लेखपत्रों की स्कैनिंग एवं इण्डेक्सिंग की प्रथम चरण की परियोजना की अवधि 06 माह तक विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने उप निबन्धक कार्यालयों में पंजीकृत विलेखों के डिजिटाइजेशन सम्बन्धी समस्त अवशेष कार्य को सम्पन्न कराने के निर्देश के साथ उप निबन्धक कार्यालय में वर्ष 2002 से 2017 तक के पंजीकृत लेखपत्रों की स्कैनिंग एवं इंडेक्सिंग की प्रथम चरण की परियोजना की अवधि 06 माह तक विस्तारित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

राजस्व ग्राम भरथापुर, ग्राम पंचायत आम्बा, जनपद बहराइच के आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में राजस्व ग्राम भरथापुर, ग्राम पंचायत आम्बा, जनपद बहराइच में आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन हेतु भूमि की व्यवस्था, आवंटन एवं उक्त भूमि पर विविध अवस्थापना सुविधाएँ प्रदान किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

ग्राम नंगला गोसाई, तहसील मवाना, जनपद मेरठ में निवासरत पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) से विस्थापित 99 हिन्दू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने ग्राम नंगला गोसाई, तहसील मवाना, जनपद मेरठ में निवासरत पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) से विस्थापित 99 हिन्दू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

ज्ञातव्य है कि यह परिवार जिस भूमि पर निवासरत हैं, वह भूमि राजस्व अभिलेखों में झील के रूप में दर्ज है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली के आदेशों के क्रम में इन परिवारों को अन्यत्र पुनर्वासित किया जाना है। जनपद कानपुर देहात की तहसील रसूलाबाद के ग्राम भैंसाया में पुनर्वास विभाग के नाम अंकित 11.1375 हे0 (27.5097 एकड़) भूमि में 50 परिवारों तथा ग्राम ताजपुर तरसौली में पुनर्वास विभाग के नाम अंकित 10.530 हे0 (26.009 एकड़) भूमि में 49 परिवारों को प्रति परिवार 0.50 एकड़ भूमि आवंटित कर पुनर्वासित किया जाना है।

उक्त भूमि को प्रीमियम अथवा लीज रेन्ट पर 30 साल के पट्टे पर निष्पादित किया जायेगा, जिसे 30-30 वर्ष के लिए नवीनीकृत करने का प्रावधान होगा। पट्टे की अधिकतम अवधि 90 वर्ष होगी। इस निर्णय से विस्थापित परिवारों को स्थायी रूप से पुनर्वासन का लाभ प्राप्त होगा।

बेसिक शिक्षा के शिक्षकों/कार्मिकों व उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद की बैठक में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों एवं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों (अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित) में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, विशेष शिक्षकों (सी0डब्ल्यू0एस0एन0), अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत वॉर्डेन, पूर्णकालिक/अंशकालिक शिक्षकों/शिक्षिकाओं एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइयों तथा उक्त कार्मिकों के आश्रितों के स्वास्थ्य के दृष्टिगत सरकारी चिकित्सालयों के अलावा निजी चिकित्सालयों में भी आई0पी0डी0 (अंतरोंगी विभाग) उपचार हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा अनुमन्य किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कैशलेस चिकित्सा सुविधा के इस निर्णय से अनुमानित 11,95,391 शिक्षक/कार्मिक लाभान्वित होंगे। इसमें बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन 4,34,226 शिक्षक, बेसिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत 13,380 शिक्षक, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के 4,72,735 शिक्षक, 1,42,929 शिक्षा मित्र, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 24,717 अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के 7,479 वॉडेन/ पूर्णकालिक/अंशकालिक शिक्षक-शिक्षिकाएं, प्रधानमंत्री पोषण योजना के 97,344 रसोईयें तथा 2,581 विशेष शिक्षक समेकित शिक्षा सम्मिलित हैं। योजना के क्रियान्वयन पर 358.61 करोड़ रुपये के वार्षिक व्ययभार का अनुमान है। यह व्यय भार प्रति शिक्षक/कार्मिक 03 हजार रुपये प्रीमियम की वार्षिक दर से अनुमानित है। योजना के क्रियान्वयन हेतु बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आय-व्ययक में आवश्यक बजट व्यवस्था करायी जायेगी।

यह सुविधा राजकीय एवं सार्वीज के साथ संबद्ध निजी चिकित्सालयों में अनुमन्य होगी, जिसकी दरें वहीं होंगी, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (एन0एच0ए0) द्वारा समय-समय पर संसूचित की जायेगी।